संख्या.सी.29011/02/2022-सीडीएन

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

***

सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक **मार्च**, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए फ़रवरी, **2022 के महीने के मासिक सार के संबंध में**

अधोहस्ताक्षरी को फ़रवरी, 2022 के महीने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों से संबंधित मासिक सार की प्रति को मंत्रिमंडल हेतु परिचालित करने का निर्देश हुआ है।

महेश कुमार

(एम. के. मीणा)

उप सचिव,भारत सरकार

फोन : 23385365

संलग्न: यथोपरि।

सेवा में

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य।

संलग्नकों सहित प्रति अग्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी सचिव (सभी मंत्रालय / विभाग)
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ: सचिव (एचई) के वरि. प्रधान निजी सचिव।

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मंत्रिमंडल हेतु फरवरी 2022 **के माह का मासिक सार:**

फरवरी, 2022 **के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां**

1. बजट घोषणाओं पर वेबिनार

शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से संबंधित बजट 2022-23 में घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 21.02.2022 को एक वेबिनार का आयोजन किया।माननीय प्रधान मंत्री ने वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित किया जिसके बाद सात समानांतर ब्रेक-अवे सत्र हुए।समापन सत्र में प्रत्येक समूह ने अपनी चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत किया।श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय; और डॉ. सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने समापन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

समग्र उद्देश्य बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के संबंध में कार्य योजना पर विचार-विमर्श करना था।बारह केंद्रीय मंत्रालयों, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी जैसे स्वायत्त निकायों, डोमेन विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, छात्रों और शिक्षकों ने दिन भर के सत्रों में भाग लिया।बजट घोषणाओं जैसे डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, डिजिटल शिक्षा की पहुंच का विस्तार और उसके लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करना, गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति देना, शहरी नियोजन और डिजाइनिंग में भारत के विशिष्ट ज्ञान को विकसित करनेआदि पर चर्चा की गई।

2. क्षमता निर्माण समिति:

क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य डॉ. आर.बालासुब्रमण्यम की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय और उसके संगठन के तहत मानव संसाधन के क्षमता निर्माण पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।इसके अलावा समिति निम्न पर भी गौर करेगी:

i. उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख कार्यों के साथ प्राथमिकता/प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना;
ii. कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) द्वारा की जाने वाली आवश्यक गतिविधियों पर विचार-विमर्श करना;
iii. बहु-विषयक शिक्षा, बहु प्रवेश और निकास प्रणाली, क्रेडिट अकादमिक बैंक, कौशल शिक्षा पर जोर देने आदि के लिए एचईआई/नियामकों के विभिन्न स्तरों पर क्षमता आवश्यकताओं का मानचित्रण;
iv. संभावित संस्थागत नेतृत्व की भूमिका के लिए संकाय तैयार करने हेतुनेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के उपायों का सुझाव देना।

3. एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)

21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के अवसर पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत ने भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए 'भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी' नाम से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है।प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने प्रमाण पत्र के साथ सेल्फी पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि स्तरों को पूरा करने और प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए अधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।

4.विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियां

विभाग ने अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; आईआईटीके निदेशक (आईआईटीमद्रास, आईआईटीमंडी, आईआईटीइंदौर और आईआईटीदिल्ली); और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी);(एनआईटी हमीरपुर; एनआईटी तिरुचिरापल्ली; डॉ बीआर अंबेडकर एनआईटी जालंधर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी उत्तराखंड, एमएनआईटी जयपुर, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी मिजोरम और एसवीएनआईटी सूरत)के निदेशकोंके लिए नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

5.एनएएसीप्रत्यायन प्रक्रिया को [संबद्ध और संघटक कॉलेज (यूजी, यूजीऔर पीजी) के लिए सेल्फस्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) के लिए एनएएसीमैनुअल)] मापदंडों की संख्या को 96 से घटाकर 57 करने के साथ-साथ क्षेत्रीय भिन्नताओं को दूर करने के लिएसरल बनाया जा रहा है।कॉलेजों की अनंतिम मान्यता के लिए नैक मैनुअल को मंजूरी दे दी गई है।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए संस्थागत विकास योजनाओं (आईडीपी) का मसौदा प्रकाशित किया है। इसी तरह, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) का मसौदा जनता की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया है।

7. 2455 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक अगले पांच वर्षों के लिए एनएमईआईसीटी योजना चरण- III को जारी रखने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।इस योजना के तहतविभिन्न डिजिटल पहलेंजैसे कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं), स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन (एफओएसएसईई), ई शोध सिंधु (ईएसएस) शोध-शुद्धि, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) आदिशुरू की गई हैं।

8. डॉ. सुभाष सरकार, माननीय राज्य मंत्री ने दिनांक 22.02.2022 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।एनईपी 2020 के कार्यान्वयन, संस्थानों द्वारा किए गए नवाचार/नई पहल, कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, सर्वश्रेष्ठविचारों को

साझा करने, रिक्तियों की स्थिति, कौशल विकास और अनुसंधान गतिविधियों के लिए उठाए गए कदम, समग्र शिक्षा और संचार कौशल के विकास की दिशा में उठाए गए कदमों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

9. एआईसीटीईद्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह पहल उच्च शिक्षा में छात्रों को स्वैच्छिकता के माध्यम से संकाय (सेवानिवृत्त/सेवारत), सेवारत और सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारियों आदि के माध्यम से उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

****